Question No. *84

Index of information

Sr. No.	Subject	Page No.
1	Reply of question no. * 84 in English	1
2	Annexure –A in English	2
3	Executive summary	9
4	Note for the Pad in English	10-11
5	Reply of question no. *84 in Hindi	12
6	Annexure- A in Hindi	13-20
7	Note for the PAD in Hindi	21-22

Executive Summary

The matter of illegal pasting of poster and flexes on public building has been considered by the State Government. For taking action against the violators for defacing public properties, the Government has notified the Haryana Prevention of Defacement of properties Act, 1989 and also made provisions in the Haryana Municipal Acts.

As per the provisions of the Acts, penal/ punishment action is to be taken against the violator for defacing the public properties. The competent authorities have also been empowered to remove the defacements.

The municipalities in the state are taking timely action against the violators and also removing the illegal posters and flexes from the public buildings.

The State Government has also enacted byelaws vide which a legal way has been given to the public for displaying advertisement which does not cause defacement in public view.

NOTE FOR PAD

To Remove Illegally Pasted posters and Flexes

The pasting of posters and flexes on public properties/ buildings by private individuals, institution, establishments and others for advertising of their own business is an illegally activities under the Haryana Prevention of Defacement of Property Act, 1989 and the Haryana Municipal Acts.

The relevant provisions of the Act of 1989 are reproduced below for ready reference:

> *3-A (1) Whoever defaces any property in public view except any board or wall provided for advertisement and publicity, by writing or marking with ink, chalk, paint or any other material, except for the purpose of indicating the name and address of the owner or occupier of such property, shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to six months or with fine which may extend to ten thousand rupees or with both:*
>
> *Provided that sign boards fixed by any person, individual or institution on their own property or property occupied by them at their cost, shall be exempted from the provisions of sub-section (1):*
>
> *Provided further that the owners or managers of the organizations making defacement of the properties for their business activities, shall be responsible for removing such defacement and the burden of proving their innocence for such defacement, shall rest on them.*
>
> *(2) Where any offence committed under sub-section (1) is for the benefit of some other person or a company or other body corporate or an association of persons, whether incorporated or not, or a political party or its candidates, then such other person and every president, chairman, director, partner, manger, secretary, agent or any other officer or person concerned with the management thereof, as the case may be, shall, unless he proves that the offence was emitted without his knowledge or consent, be deemed to be guilty of such offence.]*
>
> *5 (1) Without prejudice to the provisions of section 3A, it shall be competent for the Government to take such steps as may be necessary for erasing any writing, freeing any defacement or removing any mark from any property. The Government shall have the power to conduct or cause to conduct, through the District Magistrate concerned. Spot inspections with regard to defacement of property. If on such inspections it is found that specific permission of the owner or occupier of the property has not been obtained, action for removal of property. If on such inspections it is found that specific permission of the owner or occupier of the property has not been obtained, action for removal of defacement shall be taken forthwith at the expense of the person or person found guilty. In case the Government, before doing so, does the erasing a notice of two weeks shall be given to owner or occupier of the property to erase or remove the defacement. The expenses of removing or erasing the defacement, shall be borne by the owner or occupier found guilty.*

Under the above Act of 1989, municipalities are competent for taking action against such illegal pasting of poster and flexes on Government buildings/ properties.

The relevant provisions of The Haryana Municipal Corporation Act, 1994 are reproduced below for ready reference:

> *122 (5) No advertisement shall be erected, exhibited, fixed or retained upon or over any land, building, wall, hoarding, frame, post or structure or upon any vehicle or shall be displayed in any manner whatsoever in any place within the municipal area without the written permission of the Commissioner or the authority as specified by the Government, as the case may be.*
>
> *125. If any advertisement is erected, exhibited, fixed or retained in contravention of the provisions of section 122, the Commissioner may require the owner or occupier of the land, building, wall, boarding, frame, post or structure or vehicle upon or over or in which the same is erected, exhibited, fixed or retained, to take down or remove such advertisement or may enter any land, building, property or vehicle and have the advertisement dismantled, taken down or removed or spoiled, defaced or screened.*

The municipalities in the State are taking action against such illegal poster and flexes by way of its removal and penalizing the violators. The action taken by municipalities in last three years is compiled and placed with the reply as Annexure-A.

In addition to the above, the Government for the purpose of regulating and allowing legal way of advertisements within municipal areas has notified the Haryana Municipal Advertisement Byelaws, 2022 on 15.07.2022.

Under these byelaws, the advertisement on properties of Government entities/ agencies can only be permitted through Open E-auction for which an online portal has also been launched on 11.10.2022.

नोट फॉर पैड

अवैध तरीके से चिपकाये गए पोस्टरों तथा फ्लैक्सों को हटाना

निजी व्यक्तियों, संस्थानों, प्रतिष्ठानों और अन्य लोगों द्वारा स्वयं के व्यवसाय के विज्ञापन के लिए सार्वजनिक संपत्तियों/भवनों पर पोस्टर और फ्लैक्स चिपकाना हरियाणा संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम 1989 और हरियाणा नगर पालिका अधिनियमों के तहत एक अवैध गतिविधि है।

1989 के अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधान तत्काल संदर्भ हेतु नीचे पुनः प्रस्तुत किये है:

3–क(1) जो भी व्यक्ति सार्वजनिक मत में किसी संपति को लिखकर अथवा स्याही, चॉक, पेन्ट या किसी अन्य सामग्री से किसी प्रकार से सपंति का विरूपण करता है ऐसी संपति के मालिक अथवा अधिभोगी का नाम तथा पता दर्शाने के उद्देश्य के अतिरिक्त, छह महीने के कारावास की सजा अथवा अर्थदण्ड जो दस हजार रूपये तक बढ़ाया जा सकता है अथवा दोनों सजा का भागी होगा।

बशर्ते कि किसी भी व्यक्ति, व्यक्ति या संस्थान द्वारा अपनी संपत्ति या उनके कब्जे वाली संपत्ति पर उनकी लागत पर लगाए गए साइन बोर्ड को उप–धारा (1) के प्रावधानों से छूट दी जाएगी:

बशर्ते आगे कि संगठन के मालिक या प्रबंधन अपनी व्यावसायिक गतिविधियों के लिए संपत्तियों को विरूपण के लिए अपनी बेगुनाही साबित करने का भार उन पर होगा।

(2) जंहा उपधारा (1) के अधीन किया गया कोई अपराध किसी अन्य व्यक्ति अथवा कंपनी या अन्य निकाय नियमित अथवा व्यक्तियों की एसोसिएशन (नियमित हो अथवा नहीं) के लाभार्थ किया गया है उस स्थिति में ऐसा अन्य व्यक्ति तथा प्रत्येक समापति, अध्यक्ष, निदेशक, साझेदार, प्रबंधक सचिव एजेन्ट या अन्य कोई अधिकारी अथवा उसे प्रबंधन से संबंधित अन्य व्यक्ति जैसी भी स्थिति हो, जब तक यह प्रमाणित नहीं कर देता कि अपराध उसकी जानकारी अथवा सहमति के बिना किया गया है, उसे ऐसे अपराध का अपराधी समझा जायेगा।

5 (1) धारा 3 'क' के प्रावधानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, सरकार के लिए यह सक्षम होगा कि वह किसी भी लेखन को मिटाने, किसी भी विरूपण को मुक्त करने या किसी भी संपत्ति से किसी भी निशान को हटाने के लिए आवश्यक कदम उठा सके। सरकार के पास संबंधित जिला मजिस्ट्रेट के माध्यम से संचालन करने या कराने की शक्ति होगी। संपत्ति को विरूपण करने के संबध में स्थलों का निरीक्षण। यदि ऐसे निरीक्षणों में यह पाया जाता है कि संपत्ति के स्वामी या अधिभोगी की विशिष्ट अनुमति प्राप्त नहीं की गई है, तो संपत्ति को हटाने की कार्यवाही की जाएगी। यदि ऐसे निरीक्षणों में यह पाया जाता है कि संपत्ति के स्वामी या अधिभोगी की विशिष्ट अनुमति प्राप्त नहीं की गई है, तो दोषी पाए गए व्यक्ति या व्यक्ति के खर्चे पर विरूपण को हटाने की कार्यवाही तत्काल की जाएगी। यदि सरकार, ऐसा करने से पहले हटाती है तो संपत्ति के मालिक या अधिभोगी को मिटाने या हटाने के लिए दो सप्ताह का नोटिस देना होगा। विरूपण को हटाने या मिटाने का खर्च, दोषी पाए जाने वाले स्वामी या अधिभोगी द्वारा वहन किया जाएगा।

1989 के उपरोक्त अधिनियम के तहत, सरकारी भवनों/संपत्तियों पर अवैध रूप से पोस्टर और फ्लैक्स चिपकाने के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए नगरपालिकाऐं सक्षम है ।

हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 के प्रासंगिक प्रावधान तत्काल तत्काल संदर्भ हेतु नीचे पुनः प्रस्तुत किये हैः

122(5) कोई भी विज्ञापन, आयुक्त या सरकार द्वारा यथा विनिर्दिष्ट प्राधिकारी, जैसी भी स्थिति हो, की लिखित अनुज्ञा के बिना, किसी भूमि, भवन, दीवार, होर्डिंग, फ्रेम, खंभा या संरचना या किसी वाहन पर खड़ा नहीं किया जाएगा, प्रदर्शित नहीं किया जाएगा, लगाया नहीं जाएगा या रखा नहीं जाएगा या नगरपालिका क्षेत्र के भीतर किसी भी स्थान में किसी भी रीति जो भी हो, में प्रदर्शित नहीं किया जाएगा।

125. यदि धारा 122 के उपबंधो के उल्लंघन में, कोई विज्ञापन खड़ा किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है, लगाया जाता है या रखा जाता है, तो आयुक्त, भूमि, निर्माण, दीवार, विज्ञापन खड़ा किया गया है, प्रदर्शित किया गया है, लगाया गया है, या रखा गया है, के स्वामी या अधिभोगी से विज्ञापन नीचे उतारने अथवा हटाने की अपेक्षा कर सकता है अथवा किसी भूमि, निर्माण, संपत्ति या वाहन में प्रवेश कर सकता है, तथा विज्ञापन गिरवा सकता है, नीचे उतरवा सकता है या हटवा सकता है, खराब, विरूपित अथवा औझल करवा सकता है।

राज्य में नगर पालिका ऐसे अवैध पोस्टर और फ्लैक्स के खिलाफ कार्यवाही कर रही है और उल्लंघन करने वालों को दंडित कर रही है। पिछले तीन वर्षो में नगर पालिकाओं द्वारा की गई कार्यवाही को संकलित किया गया है और उत्तर के साथ अनुलग्नक–'क' के रूप में रखा गया है।

उपरोक्त के अलावा, सरकार ने नगरपालिका क्षेत्रों के भीतर विज्ञापनों के कानूनी तरीके से नियमित करने और अनुमति देने के उद्देश्य से हरियाणा नगरपालिका विज्ञापन उपनियम, 2022 को 15.07.2022 को अधिसूचित किया है।

इन उपनियमों के तहत, सरकारी संस्थाओं/एजेंसियों की संपत्तियों पर विज्ञापन की अनुमति केवल खुली ई–नीलामी के माध्यम से दी जा सकती है, जिसके लिए 11.10.2022 को एक ऑनलाईन पोर्टल भी लॉन्च किया गया है।